प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

24 दिसंबर 2020

रिज़र्व बैंक बुलेटिन - दिसंबर 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपने मासिक बुलेटिन के दिसंबर 2020 के अंक को जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21: 2-4 दिसंबर 2020 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प, एक भाषण, आठ लेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

ये आठ लेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. वास्तविक समय स्थानिक गति को कैप्चर करने के लिए आर्थिक गतिविधि का संकेतक; III. सरकारी वित्त 2020-21- छमाही समीक्षा; IV. भारत में ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति गतिशीलता; V.COVID-19 के समय में विनिमय दर की अस्थिरता का प्रबंधन; VI. सेवाएं और आधारभूत संरचना संभावना सर्वेक्षण: हालिया रूझान; VII. बैंक ऋण सर्वेक्षण- हालिया रुझान; VIII. भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमीपन।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

पिछले महीने के लेख में प्रस्तुत किए गए मूल्यांकन के बाद से, अधिक सबूत दिए गए हैं यह दिखाने के लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था COVID-19 के गहरे खाई से बाहर निकल रही है तथा एक ऐसी गति से प्रतिबिंबित हो रही है जो अधिकांश भविष्यवाणियों को पूरा करती है। नवंबर 2020 में कृषि और विनिर्माण गतिविधियों में तेजी के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार जारी रहा। ब्याज दरों में समाविष्ट वित्तीय स्थितियां शायद दशकों में सबसे आसान स्तर पर हैं। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, सभी हितधारकों द्वारा निरंतर प्रयासों से भारत को तेज़ वृद्धि प्रक्षेपवक्र पर रखा जा सकता है।

II वास्तविक समय स्थानिक गति को कैप्चर करने के लिए आर्थिक गतिविधि का संकेतक

इस लेख का उद्देश्य भारत में राज्य स्तर पर आर्थिक गतिविधि की गतिशीलता को दैनिक उच्च आवृत्ति चर के साथ एक संयोग सूचकांक (सीआई) का निर्माण करना है।

मुख्य बातें :

- COVID-19 महामारी ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है कि कैसे नीति निर्धारक तेजी से विकसित होने वाली आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में आर्थिक डेटा की निगरानी करते हैं और उचित और त्वरित नीति प्रतिक्रियाओं को शुरू करने के लिए उप-राष्ट्रीय रुझानों को बदलते हैं।

- इस लेख का उद्देश्य भारत में राज्य स्तर पर आर्थिक गतिविधि की गतिशीलता को दैनिक उच्च आवृत्ति चर के साथ एक संयोग सूचकांक (सीआई) का निर्माण करना है। सीआई का निर्माण चार संकेतकों के साथ किया गया है जो मांग और आपूर्ति की गतिशीलता के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य स्तर पर दैनिक आवृत्ति पर डेटा की उपलब्धता पर आधारित होते हैं: (i) कुल वाहन पंजीकरण; (ii) बिजली की खपत; (iii) वायु गुणवत्ता सूचकांक; और iv) गूगल और एपल गतिशीलता डेटा।
- राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद अप्रैल में सभी क्षेत्रों के राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट देखी गई। इसके बाद, सभी क्षेत्रों के सीआई ने रुक-रुक कर डाउनवर्ड गतिविधियों के साथ यद्यपि, बहाली का प्रदर्शन किया।
- सीआई के अनुसार, उत्तरी क्षेत्र में जून में सबसे तेज रिकवरी देखी गई, इसके बाद जुलाई में सकारात्मक गति देखी गई, जबकि पश्चिमी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे धीमी रिकवरी देखी गई, जो जुलाई के अंत और अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी रही थी।
- विशेष रूप से, सभी क्षेत्रों के राज्यों के लिए सीआई ने अक्टूबर में तेज वृद्धि दर्ज की। नवंबर की पहली छमाही में कुछ गिरावट दर्ज की गई थी, तथापि अधिकांश राज्यों में दूसरी छमाही में गति सकारात्मक रही और पुनर्जीवित हुई।
- इसके अलावा, सीआई का औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के साथ सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध है।

III. सरकारी वित्त 2020-21- एक छमाही समीक्षा

राजकोषीय आंकड़ों की उच्च आवृत्ति रिपोर्टिंग विश्व स्तर पर एक सर्वोत्तम अभ्यास है और जी -20 डेटा अंतराल पहल के तहत एक आवश्यकता है। यह लेख छमाही आवृत्ति पर सरकारी वित्त - केंद्र, राज्यों और संयुक्त पर संकलन और विश्लेषण की श्रृंखला पर तीसरा है।

मुख्य बातें:

- 2020-21 के बजट में केंद्र और राज्यों द्वारा प्रस्तुत राजस्व और व्यय का अनुमान COVID-19 के प्रकोप और आर्थिक गतिविधियों में परिणामी मंदी के कारण समाप्त हो गया है।
- आर्थिक मंदी का प्रभाव राजस्व पक्ष पर गंभीर रहा है, जबकि व्यय काफी हद तक बाधित है। उम्मीद की किरण यह है कि यह प्रभाव ति1: 2020-21 में नीचे चला गया है जिसमें ति2 में रिकवरी के संकेत है।
- सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य) राजकोषीय घाटे में चालू वर्ष की पहली छमाही में सामान्य बिल्ड-अप की तुलना में तेज वृद्धि देखी गई है।
- आगे बढ़ते हुए, ति1 में पहले से ही प्राप्त किए गए सरकारी वित्त पर COVID-19 के सबसे गंभीर प्रभाव के साथ, केंद्र और राज्यों के लिए काउंटर-साइक्लिकल राजकोषीय समर्थन जारी रखने की गुंजाइश है जो रिकवरी की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

IV. भारत में ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति की गतिशीलता

अखिल भारतीय के साथ-साथ राज्य स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए नाममात्र सहारे के रूप में एक मुद्रास्फीति लक्ष्य की प्रासंगिकता को मान्य करने के लक्ष्य के साथ, यह लेख नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रृंखला के लिए ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति की गतिशीलता का उनके चालकों, प्रवृत्ति, अस्थिरता, दृढ़ता और अभिसरण के संदर्भ में अध्ययन करता है।

मुख्य बातें:

- भारत में ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति प्रवृत्ति, चक्र, दृढ़ता और अस्थिरता - छिटपुट मतभेद के बावजूद , जो लंबे समय तक नहीं रहते हैं के संदर्भ में इसी तरह की गतिशीलता का प्रदर्शन करती है।
- अल्पावधि में देखे गए ग्रामीण-शहरी मुद्रास्फीति अंतर सीपीआई के विभिन्न घटकों द्वारा संचालित होते हैं और वे प्रकृति में क्षणिक होते हैं, जो उनके बीच लंबे समय से चल रहे एकीकरण संबंधों की उपस्थिति और संरेखण को पुनर्स्थापित करने में सुधार प्रक्रिया पर एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण त्रुटि अनुभवजन्य निष्कर्षों से पता चलता है।
- राज्य स्तर पर भी, β अभिसरण परीक्षण के परिणाम से पता चलता है कि शहरी और ग्रामीण मुद्रास्फीति दर समय के साथ अभिसारित हो जाती हैं।

V. COVID-19 के समय में विनिमय दर की अस्थिरता का प्रबंधन

यह लेख COVID-19 के समय में देखी गई विनिमय दर की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक के उपायों की प्रभावकारिता का आकलन करने का प्रयास करता है।

मुख्य बातें:

- COVID -19 के प्रकोप के मद्देनजर, उभरते बाजार की मुद्राओं में काफी अस्थिरता देखी गई, जिसकी शुरुआत मार्च 2020 में बृहद जोखिम वाले बहिर्वाह से हुई, जिसमें भारतीय रुपये (आईएनआर) सहित बड़े पैमाने पर मूल्यह्रास दबाव शामिल थे।
- महामारी द्वारा वित्तीय स्थिरता और वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न होने पर, रिज़र्व बैंक की प्रतिक्रिया थी कि 'अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो आवश्यक है वह करें'।
- रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों ने बाजार की अस्थिरता को रोकने में मदद की और वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरों को कम किया। विभिन्न प्रकार के संकेतकों द्वारा मापी जाने वाली अस्थिरता, मार्च में उछाल के बाद जल्दी से सामान्य हो गई और अतीत में तनाव की घटना की तुलना में कम रही।

VI. सेवाएँ और आधारभूत संरचना संभावना सर्वेक्षण: हालिया रुझान

यह रिज़र्व बैंक की त्रैमासिक सेवाएं और आधारभूत संरचना संभावना सर्वेक्षण (एसआईओएस) पर पहला लेख है, जो 2014-15 की पहली तिमाही के बाद से आयोजित किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण निकट अवधि में सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्र की कंपनियों के अपने कार्यनिष्पादन और व्यावसायिक

संभावनाओं के बारे में धारणाएं प्रदान करता है। अपनी आरंभ के बाद से यह लेख, सर्वेक्षण और प्रमुख मापदंडों में संचलन का विवरण प्रस्तुत करता है।

मुख्य बातें:

- अधिकांश मापदंडों के लिए, व्यक्त अपेक्षाएं, सामान्य रूप से व्यावसायिक अपेक्षाओं में आशावाद पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने वाले आकलन से अधिक हैं।
- टर्नओवर संबंधी मनोभावों ने वित्त वर्ष 2019-20 के अंत तक आशावाद दर्शाया लेकिन महामारी की स्थिति के कारण 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान इसमें गिरावट आई।
- सेवाओं और आधारभूत संरचना कंपनियों ने महामारी के प्रकोप तक निरंतर वेतन दबाव महसूस किया। इसके बाद, वेतन संबंधी व्यय में गिरावट का आकलन किया गया था क्योंकि कॉरपोरेट्स ने एक तिमाही में कम कर्मचारियों को काम के लिए रखा।
- प्रतिवादियों ने 2019-20 तक लगातार इनपुट लागत दबाव की सूचना दी। बाद में इनपुट लागत पर बेहतर धारणाओं के साथ, बिक्री की कीमतों में भी गिरावट देखी गई।
- कंपनियों की समग्र मनोभाव आशावादी रहीं, हालांकि 2020-21 की पहली तिमाही में महसूस किए गए COVID -19 महामारी के गंभीर प्रभाव से पहले धीरे-धीरे सौम्य हुआ था। इसके बाद कारोबारी मनोभाव में बहाली देखी गयी लेकिन अभी तक महामारी-पूर्व के स्तर तक नहीं पहुंच पायी है।

VII. बैंक ऋण सर्वेक्षण-हालिया रुझान

यह लेख बैंक ऋण सर्वेक्षण (बीएलएस) का सार परिणाम प्रस्तुत करता है, जो कि जुलाई-सितंबर 2017 के बाद से रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित किया जा रहा एक पूर्वानुमान तिमाही सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्रेडिट बाज़ार की स्थितियों और ऋण देने के प्रथाओं के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त करना है।

मुख्य बातें:

- यह सर्वेक्षण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रेडिट में संभावित गति के बारे में शुरुआती संकेत प्रदान करता है।
- औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण से उधारकर्ताओं की धारणाओं और विनिर्माण क्षेत्र के बीएलएस में प्रतिबिंबित उधारदाताओं के मनोभाव में एक व्यापक संबंध देखा गया है।
- COVID-19 महामारी के कारण अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में प्रतिकूल स्थिति के बाद उधार देने की शर्तों पर बैंकरों के मनोभाव में सुधार हुआ है।

VIII. भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमीपन

यह लेख छह व्यापक क्षेत्रों (अर्थात, धन और बैंकिंग, मूल्य, औद्योगिक उत्पादन, व्यापारिक कारोबार, सेवाओं और भुगतान के वैकल्पिक तरीकों) को कवर करने वाले 80 समष्टि आर्थिक चर के लिए मासिक मौसमी कारक प्रस्तुत करता है।

मुख्य बातें:

- औद्योगिक उत्पादन, मौद्रिक / बैंकिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के संकेतक ने मार्च के आसपास मौसमी सुधार दर्ज किया हैं, जबकि अधिकांश मूल्य संकेतकों ने मार्च-मई में मौसमी उतार दर्ज किया है।
- भुगतान माध्यमों के भीतर, थोक लेनदेन से संबंधित लिखत मार्च के दौरान अपने चरम पर थी, जो वार्षिक वित्तीय लेखाबंदी पर ऑनलाइन अंतरण के व्यापक उपयोग का संकेत देते हैं, जबकि खुदरा भुगतान लिखतों के मामले में, त्योहारों के दौरान मौसमी चरम देखे गए।

अजीत प्रसाद
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/824